

आदवासी संपत्तियों पर सुरक्षा शविरि

चर्चा में क्यों?

संविधान की एक रपौरट के अनुसार, 2019 के बाद छत्तीसगढ और झारखंड में अधिकांश सुरक्षा शविरि [आदवासियों](#) की नजी या सामुदायिक संपत्तियों पर उनकी सहमति के बिना तथा मौजूदा कानूनों का गंभीर उल्लंघन करते हुए स्थापति कयि गए हैं।

मुख्य बदि

- छत्तीसगढ और झारखंड में आदवासी समुदायों की सहमति के बिना स्थापति अर्द्धसैनिक शविरिों का प्रसार, जनिका उद्देश्य आदवासियों के जीवन तथा संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर [खनन कार्यों](#) एवं [कॉरपोरेट हतियों](#) को [सुवधाजनक](#) बनाना है।
 - शविरिों के वरिद्ध शांतपूरण लोकतांत्रिक वरिध को नज़रअंदाज़ कयि गया है या लाठीचार्ज, स्थलों को जलाने और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी जैसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करके दबा दयि गया है।
- इनमें से अधिकांश शविरि ऐसे क्षेत्रों में स्थापति कयि गए हैं, जो वर्तमान में [संधारणीय खनन प्रबंधन योजना 2018](#) के अनुसार [संरक्षण या खनन नषिध क्षेत्र](#) में आते हैं।
- रपौरट में कानून का सम्मान करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लयि [पंचायत \(अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार\) अधनियम, 1996](#) तथा [वन अधिकार अधनियम, 2006](#) के कार्यान्वयन का आह्वान कयि गया है।³

पंचायत (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार) अधनियम, 1996

- परचिय:
 - PESA अधनियम 1996 में [“पंचायतों](#) से संबंघति संवधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितारति करने के लयि” अधनियमति कयि गया था।
 - संवधान के भाग IX में अनुच्छेद 243-243ZT शामिल हैं, जसिमें नगर पालिकाओं और सहकारी समतियों से संबंघति प्रावधान हैं।
- प्रावधान:
 - अधनियम के तहत, अनुसूचति क्षेत्र वे हैं जो अनुच्छेद 244(1) में संदर्भति हैं, जसिमें कहा गया है कि [पाँचवीं अनुसूची](#) के प्रावधान असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचति क्षेत्रों एवं अनुसूचति जनजातियों पर लागू होंगे।
 - पाँचवीं अनुसूची में इन क्षेत्रों के लयि अनेक वशिष प्रावधान कयि गये हैं।
 - **दस राज्य-** आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हमिाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना ने [पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को अधसूचति](#) कयि है, जो इनमें से प्रत्येक राज्य के कई ज़िलों को (आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से) कवर करते हैं।

वन अधिकार अधनियम, 2006

- **वन अधिकार अधनियम (FRA), 2006** को वन में रहने वाले [अनुसूचति जनजातियों](#) और अन्य पारंपरिक वनवासियों को [वन भूमि](#) पर औपचारिक रूप से वन अधिकारों तथा कब्जे को मान्यता देने एवं प्रदान करने के लयि पेश कयि गया था, जो इन वनों में पीढ़ियों से नवास कर रहे हैं, भले ही उनके अधिकारों को आधिकारिक तौर पर दस्तावेज़ति नहीं कयि गया हो।
- इसका उद्देश्य औपनविशक और उत्तर-औपनविशक भारत की वन प्रबंधन नीतियों के कारण वन-नवासी समुदायों द्वारा झेले गए [ऐतिहासिक अन्याय को संबोधति](#) करना था, जो वनों के साथ उनके दीर्घकालिक सहजीवी संबंधों को स्वीकार करने में वफिल रहे।
- इसके अतरिकित, अधनियम का उद्देश्य [वनवासियों को](#) वन संसाधनों तक पहुँच और उनका स्थायी उपयोग करने, जैवविधिता तथा पारस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने एवं उन्हें गैरकानूनी बेदखली व वसिस्थापन से बचाने के लयि [सशक्त](#) बनाना था।

